nwda.gov.in

पाताल में जल संकट में कल

एनसीआर के शहरों की जल प्रणालियां बदलती परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। अधिकांश शहरों में वर्षा ठीक हो रही है, दिल्ली में पिछले वर्ष बाढ़ आई। लेकिन सारे शहर जल संकट से जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कोई भी शहर ऐसा नजीर देने वाला नहीं है कि वहां डार्क जोन से उभरकर शहर ने जल संचयन कर भूजल की स्थिति सुधार ली हो। वर्षा के समय अधिक से अधिक जल संचित करके मिसाल पेश की हो। पानी पाताल में पहुंच रहा है और हर शहर संकट की ओर बढ़ रहा है। वर्षा जल संग्रहण के लिए न ही सरकारी एजेंसियां जागरूक दिखती हैं और न ही अपने-अपने स्तर पर आरडब्ल्यूए/एओए और उद्यमी व कारोबारी एसोसिएशन। एनसीआर में मानसून भी दहलीज पर पहुंच चुका है, ऐसे में यही सवाल उठता है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी वर्षा का अमूल्य जल बर्बाद हो जाएगा? जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों को भूजल स्तर ऊपर उठाने के लिए वर्षा जल संग्रहण पर जोर देना चाहिए, लेकिन स्थिति इसके उलट है? आखिर इन विभाग और अधिकारियों की जल संरक्षण के प्रति क्यों है ऐसी अन्यमनस्कता? एनसीआर में वर्षा जल संग्रहण के लिए क्या किए जाने चाहिए ठोस उपाय? कैसे अधिकाधिक वर्षा जल का हो भूजल स्तर बढ़ाने में इस्तेमाल? इसी की पड़ताल करना हमारा आज का मुद्दा है :

डा. वीके गुप्ता
सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा

पार्कों को तालाब मानकर करें जल संचयन

जिस तरीके से भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, यदि वर्षा जल संचयन के ऊपर जोर नहीं दिया गया तो आने वाले कुछ वर्षों में ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पानी के लिए लड़ाई होगी। कुछ इलाकों में पानी के लिए मारा-मारी शुरू भी हो चुकी है। गुरुग्राम के कई इलाकों में भूजल स्तर का नामोनिशान नहीं। पिछले कई साल से पूरा जिला डार्क जोन में है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी भयावह स्थिति आने वाले दिनों में गुरुग्राम में बनने वाली है। यही हाल दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा एवं सोनीपत में धीरे-धीरे होता जा रहा है। गुरुग्राम बहुत पुराना शहर नहीं है। 1980 के पहले यह कुछ भी नहीं था। यानी तीन-चार दशक में ही पूरी तस्वीर बदल गई। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले दो-तीन दशक के दौरान क्या होगा? यमुना में इतना पानी नहीं होगा कि जिससे कि सभी की प्यास बुझ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सहित आसपास के कई जिलों में यमुना के अलावा कहीं से भी पानी ला नहीं सकते। यदि पानी की लाइनें किसी कारण से बाधित हो जाएं फिर क्या होगा। इतनी बड़ी आबादी की प्यास कैसे बुझेगी। कभी किसी ने सोचा है। नहीं सोचने का ही नतीजा है कि भूमिगत जल स्तर के ऊपर ध्यान न देना। यदि इस बारे में शासन-प्रशासन सोचता तो भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास होता। मेरा मानना है कि फिलहाल भूमिगत जल स्तर बढ़ाने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। शहरी क्षेत्रों के अधिकतर तालाबों को भरकर ऊंची-ऊंची इमारतें बना दी गईं। इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब उन इमारतों को तोड़ना आसान नहीं है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ही जल संचयन का सबसे बड़ा हथियार है। इसी के ऊपर जोर देने की आवश्यकता है। दिल्ली-एनसीआर के लिए एक बाडी का गठन किया जाए। उस बाडी की जिम्मेदारी केवल रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित कराने व आगे रखरखाव के ऊपर ध्यान देने की रहे। अगले कुछ सालों के दौरान ही तस्वीर बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहले की अपेक्षा बहुत कम वर्षा होती है। पहले वर्षा का पानी तालाबों में जमा होता था। इससे अधिक जो पानी होता था वह यमुना तक पहुंचता था। इससे सभी इलाके में भूजल स्तर ऊंचा रहता था। तालाबों के न रहने से पानी कहीं जमा नहीं हो पाता है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में जितने भी पार्क हैं, उन्हें भी तालाब मान लिया जाए यानी पार्क सड़कों से कुछ नीचे हों। इससे इलाके का पानी पार्कों तक पहुंचेगा। पार्कों में आवश्यकतानुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित किया जाए। इससे सभी इलाकों में वर्षा के पानी का संचयन आसानी से हो सकेगा। सोसायटियों से लेकर बड़े साइज के मकानों के परिसर में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम न केवल विकसित किए जाएं बल्कि उनके रखरखाव के ऊपर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए।

फिलहाल स्थिति यह है कि जिन सोसायटियों में सिस्टम विकसित हैं उनमें से अधिकतर में सिस्टम चालू हालत में नहीं। आरडब्ल्यूए या कालोनाइजर या फिर आम लोग केवल प्रशासन को दिखाने के लिए नहीं बल्कि जल संचयन को ध्यान में रखकर जब सिस्टम विकसित कराएंगे फिर वे उसके रखरखाव के ऊपर ध्यान भी रखेंगे। सभी को जिम्मेदारी समझनी होगी। प्रशासन समय-समय पर वाटर आडिट कराए। इससे पता चलता रहेगा कि किस इलाके में किस वजह से भूजल स्तर नीचे गया है। जब कारण सामने आ जाए फिर उसके ऊपर काम करे। राजस्थान में पानी की भारी कमी थी। जिन इलाकों में तालाबों के ऊपर जोर दिया गया, उन इलाकों की तस्वीर बदल चुकी है। इसके लिए सभी ने मिलजुलकर प्रयास किया। केवल शासन-प्रशासन के चाह लेने से ही भूजल स्तर ऊंचा हो जाएगा, ऐसा सोचना गलत है। जल है तो कल है। जब जल ही नहीं बचेगा फिर विकास का कोई मतलब नहीं। एसटीपी का पानी कृषि एवं भवन निर्माण में उपयोग किया जाए। कृषि एवं भवन निर्माण के लिए किसी भी हाल में भूमिगत जल का उपयोग नहीं होना चाहिए।

जैसा कि लेखक ने आदित्य राज को बातचीत में बताया